



तेजस्वी यादव सोमवार देर शाम को पटना खाना हो गए, अपनी दिल्ली यात्रा को सफल आंकते हुए

दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावीरु से मुलाकात करके और सीटों के बँटवारे पर मोटा-मोटी सहमति प्राप्त करके

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव सोमवार शाम पटना लौटे और सूत्रों के अनुसार, वे बातचीत से संतुष्ट और सकारात्मक मूड में हैं।
तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की, क्योंकि दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात नहीं हो पाई। तेजस्वी ने कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ भी बैठक की, जिसमें दोनों दलों के बीच सीटों का मोटा-मोटी

- हालांकि, तेजस्वी की राहुल गांधी से रुबरु बातचीत नहीं हुई, किन्तु फोन पर आरजेडी व कांग्रेस के बीच सीटों के बँटवारे का फार्मूला तय हो गया।
- फार्मूले के अनुसार, कांग्रेस को इकसठ सीटें मिलेंगी जो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, कांग्रेस के लिए। क्योंकि गत चुनाव में कांग्रेस को सत्तर सीटें मिली थीं और वह केवल सत्रह सीटें जीत पाई थी।
- आरजेडी ने कांग्रेस को इतना अधिक एडजस्ट इसलिए भी किया, क्योंकि राहुल, लालू, राबड़ी व तेजस्वी के साथ डटकर खड़े रहे, जब न्यायालय ने इन तीनों के खिलाफ आरोप फाइल करने का निर्णय लिया।
- अब पटना में ही तेजस्वी को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, क्योंकि तेजस्वी दिल्ली से पटना खाना हो चुके हैं।

खाका तय हो गया।
कांग्रेस को इस समझौते में 61 सीटें मिली हैं, जो हर लिहाज से अच्छी और सम्मानजनक संख्या है। उन्होंने कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब एनडीए में “बिग ब्रदर” नहीं रहे नीतीश

संभावना है, अगर एनडीए जीता तो भी नीतीश को शायद मु.मंत्री न बनाया जाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। अगर राजनीति को धारणाओं का खेल कहा जाए, तो आज घोषित हुई एनडीए की सीट बंटवारे की व्यवस्था जेडीयू नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नकारात्मक संदेश लेकर आई है, क्योंकि भाजपा और जेडीयू, दोनों ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।
पिछले चुनावों में, जेडीयू ने हमेशा भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिससे कुमार का गठबंधन में 'बड़े भाई' वाला दर्जा कायम रहता था। अपने राजनीतिक जीवन के इस पतझड़ में उस दर्जे से वंचित होना उनके लिए एक झटका माना जा रहा है। सीटों के बंटवारे के इस घटनाक्रम को इस संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है कि आगामी चुनावों में एनडीए की जीत होने पर भी नीतीश कुमार को शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए।

- नीतीश की पार्टी जद (यू) और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब तक हमेशा से ही नीतीश की पार्टी जद (यू) को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलती थीं, चाहे एक ही सीट अधिक क्यों न हो। शेष सीटें अन्य दलों को मिली हैं, इस लिहाज से भाजपा का पलड़ा भारी है।
- निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर बड़ी सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, नीतीश को मालूम होना चाहिए, जद (यू) की 101 सीटों की तुलना में भाजपा 130 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोजपा (गिरांग गुट) की 29 सीटें भी भाजपा की ही मानी जानी चाहिए।

राजनीतिक विरोधियों ने पहले ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि जेडीयू की 101 सीटों के मुकाबले, भाजपा असल में 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।” जाहिर है, उनका इशारा चिराग पासवान की एलजेपी-आर को दी गई 29 सीटों की ओर था। याद दिला दें कि 2020 के चुनावों में, चिराग पासवान ने नीतीश की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। एनडीए द्वारा घोषित समझौते के अनुसार, जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा के दल छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
इधर, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भविष्यवाणी की है कि चुनावों के बाद जेडीयू के टूटने की पूरी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोल्डिफ कफ सिरप बनाने वाली कम्पनी बंद

चेन्नई, 13 अक्टूबर। कोल्डिफ कफ सिरप से हुई मौतों के बाद तमिलनाडु सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कफ सिरप पीने से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 22 बच्चों की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कंपनी के खिलाफ यह कड़ा कदम

- तमिलनाडु सरकार ने इस कम्पनी, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

उठाया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। कोल्डिफ कफ सिरप में अत्यधिक मात्रा में डायएथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) होने के संकेत मिले हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में दवाइयां बनाने वाली सारी कंपनियों को भी जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं, अदालत ने श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश एसआईटी ने रंगनाथन को गिरफ्तार किया था।

मदन राठौड़ की पत्नी बीमार, हैलीकॉप्टर से जयपुर ले गये

पाली, 13 अक्टूबर (नि.सं.)। भाजपा प्रदेशध्यक्ष मदन राठौड़, पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर हैलीकॉप्टर से पाली पहुंचे तथा न्यूरो फिजिशियन को दिखाने के लिए पत्नी को हैलीकॉप्टर से ही जयपुर लेकर गए। मदन राठौड़ के साथ में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल भी थे।
पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, एसपी आदर्श

- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्हें जयपुर में न्यूरो फिजिशियन को दिखायेंगे।
- सिद्ध सहित, बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
भाजपा प्रदेशध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी ऊषा राठौड़ का उपचार करने वाले बांगड़ हॉस्पिटल के डॉ प्रवीण गर्ग, राकेश सोनी, विकास गहलोत और सेवानिवृत्त प्रधान मैडिकल ऑफिसर की सलाह के बाद, उन्हें न्यूरो फिजिशियन को दिखाने के लिए जयपुर रेफर किया गया।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ अपनी पत्नी को न्यूरो फिजिशियन को दिखाने के लिए हैलीकाप्टर से अपने साथ जयपुर के लिए लेकर खाना हुए।

सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही असंतोष फूट पड़ा एनडीए में

अमित शाह जल्दी ही पटना जाएंगे और सब कुछ ठीक करके ही लौटेंगे

- पार्टी के अंतरंग सूत्रों ने कहा कि एनडीए में हालात बेहद विस्फोटक हैं भाजपा-जद (यू) नेतृत्व को आपात बैठक बुलानी पड़ रही है।
- भाजपा के केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान पर प्रत्याशी चयन में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं जद (यू) के वरिष्ठ मंत्री जय कुमार सिंह ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा व ललन कुमार सिंह पर टिकट बेचने का आरोप लगाया।
- विशेषज्ञों ने बताया कि दोनों दलों के कई नेता हैं, जिनके टिकट कटने जा रहे हैं और ये सभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं।

गठबंधन को अपनी उम्मीदवारों की अंतिम सूची स्थगित करनी पड़ी। पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की कि सीट आवंटन को लेकर न केवल गठबंधन न केवल के भीतर बल्कि दलों के अंदर भी संघर्ष

इतना बढ़ गया है कि स्थिति विभाजन की कगार पर पहुँच गई। इसने भाजपा और जेडीयू नेतृत्व को आपात समीक्षा बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका व चीन में ट्रेड वॉर और भीषण होने का लाभ सीधे भारत को हो रहा है

अमेरिका द्वारा चीन पर सौ प्रतिशत टैरिफ और लगाने से चीनी माल अमेरिका में बहुत महंगा हो गया

- चीन पर एक सौ तीस प्रतिशत टैरिफ लगाये हैं ट्रंप ने और भारत पर पचास प्रतिशत। अब तक चीन छाया हुआ था अमेरिका में, खिलौनों, जूता-चप्पल व टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में।
- अब भारत के पास स्वर्णिम अवसर है चीन द्वारा छोड़े गए मैदान पर कब्जा करने का। ऐसी आशा की जा रही है कि अमेरिका से ऑर्डर की बाढ़ आएगी भारत के पास। अगर भारत के व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता व डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं देते हैं तो भारत स्थाई लाभ लेने की पोजीशन में रहेगा।

हासिल कर रहे हैं।
भारत के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। अमेरिका को होने वाला भारत का निर्यात पहले से ही 86.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है, और अमेरिकी रिटेलर और निर्माता अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में यह बदलाव भारतीय व्यवसायों के लिए नए ऑर्डरों में तेज वृद्धि का कारण बन सकता है। भारतीय निर्यात संगठन

चीन के उस फ़ैसले के बाद आई है, जिसमें उसने दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई थी। ये धातुएं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और अक्षय ऊर्जा उद्योगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसके जवाब में वाशिंगटन ने भी चीनी उत्पादों पर और ज़्यादा शुल्क लगाने और सॉफ़्टवेयर निर्यात नियंत्रण सख्त करने का निर्णय लिया है, जिससे यह व्यापारिक संघर्ष और तेज हो गया है। लेकिन जहाँ दुनिया इस कारण होने वाली आपूर्ति बाधाओं को लेकर चिंतित है, वहीं भारत इस स्थिति से उत्पन्न व्यापारिक बदलाव का लाभ उठा सकता है। अमेरिकी बाजार में चीनी वस्तुएं अब बहुत महंगी हो जाएंगी, जबकि भारतीय उत्पादों पर तुलनात्मक रूप से केवल 50 प्रतिशत शुल्क लगेंगा। इससे भारतीय सामान अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन को भी प्रेरित कर सकता है, जिसमें भारत मध्यम और उच्च मूल्य वाले मैनुफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में, जो अब तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन विद्वानों को अर्थशास्त्र का नोबेल

स्टॉकहोम, 13 अक्टूबर। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को साल 2025 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान जोएल मोकिर,फिलिप अधियन और पीटर होविट को देने की घोषणा की।
अकादमी ने इन अर्थशास्त्रियों के नामों की घोषणा करते हुए कहा” मोकिर

- ये तीनों हैं जोएल मोकिर, फिलिप अधियन और पीटर होविट।

ने हमें यह बताया कि कैसे नवाचार प्रगति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ ती है और हम सभी को प्रभावित करती है। नए उत्पाद और उत्पादन विधियाँ पुराने उत्पादों और उत्पादन विधियों का स्थान ले लेती हैं। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास चलता रहता है।
जोएल मोकिर एक डच मूल के अमेरिकी-इजरायली आर्थिक इतिहासकार हैं, जिनका जन्म नीदरलैंड के लीडेन में एक यहूदी परिवार में हुआ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय कहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। –बर्क

विश्वसनीयता खोता चुनाव आयोग

भारतीय संविधान के अनुसार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इसीलिए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और सरकार के अधीन नहीं रखा गया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकार के सारे अधिकारी/कर्मचारी भी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। सामान्यतया चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा है। यदा–

कदा, चुनाव आयोग से सत्ताधारी दल के पक्ष में निर्णय लेने के आरोप अवश्य लगे हैं।

इस प्रकार के आरोप दो परिस्थितियों में अधिक लगे हैं।

पहला, आदर्श आचार संहिता की सत्ता धारी दल के नेताओं द्वारा अवहेलना करने पर, चुनाव आयोग ने नरमी दिखाई, जबकि इसी प्रकार का उल्लंघन विपक्षी दलों द्वारा किए जाने पर निर्वाचन आयोग ने पूरी सख्ती के साथ विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है।

दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव के लिए तारीख तय करने की अधिसूचना जारी करते समय। देखा गया है कि चुनाव की अधिसूचना इस प्रकार जारी की जाती है कि सरकार को लोक लुभावनी घोषणाएं करने का पर्याप्त अवसर मिले। हालां के कुछ वर्षों में इस प्रकार के आरोपों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में कार्रवाई करने के प्रश्न पर में चुनाव आयुक्तों में भी मतभेद हुए। ऐसे ही एक प्रसंग में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से इस धारणा को बल मिला कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन) की घोषणा 25 जून 2025 को की। घोषणा के साथ ही बिहार की मतदाता सूचियां के विशेष गहन परीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि बिहार में चुनाव नवंबर 2025 में संभावित थे। समय की अत्यधिक कमी, बाढ़ की स्थिति और एस आई आर की वैधानिकता को लेकर कई राजनीतिक दलों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स तथा चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं ।

सुप्रीम कोर्ट में अनेक बार सुनवाई हुई और हर बार किसी–न–किसी बहाने से चुनाव आयोग तिथि बदलवाने में सफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन एस आई आर पर नहीं देने के कारण निर्वाचन आयोग एस आई आर की प्रक्रिया 25 जून से निरंतर चलती रही। कई स्वतंत्र पत्रकारों एवं टीवी संवाददाताओं द्वारा यह निरंतर दिखाया गया कि किस प्रकार बी एल ओ अपने ही स्तर पर मतदाताओं के हस्ताक्षर करके मतदाता सूची में नाम अंकन करने के लिए फॉर्म भर रहे थे। इनकी कोई रसीद भी मतदाताओं को नहीं दी जा रही थी। इन सबके प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने पर भी न्यायालय ने किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया। केवल यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों के साथ ही ‘आधार’ की भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए थे।

निर्वाचन आयोग के 25 जून के निर्देशों के अनुसार बिहार के सभी मतदाताओं को एक फॉर्म भरकर देना था। 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं थे उन्हें तो अपने एवं माता–पिता के भारत के नागरिक होने का प्रमाण भी देना था। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें न तो वोटर आईडी कार्ड सम्मिलित था, न ही आधार कार्ड। निर्वाचन आयोग ने एस आई आर के पीछे जो मुख्य कारण बताए, उनमें अवैध रूप से भारत में रह रहे मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम हटाना एवं सभी भारतीय नागरिकों के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करना था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने एस आई आर को मतदाता सूचियां के ‘शुद्धिकरण’ का नाम दिया। तीन माह में एस आई आर की प्रक्रिया को बिहार में जिस प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया गया, उसको देखकर तो केवल यही कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के बजाय इसका ‘अशुद्धिकरण’ कर दिया है। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के अनुसार एस आई आर का मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना था।आज तक आयोग यह नहीं बता पाया कि जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए उनमें से कितने घुसपैठिए थे?

कई ऐसे लोगों के नाम अवश्य हटा दिए गए जो वैध रूप से भारत के नागरिक थे और कई वर्षों से मतदान में हिस्सा ले रहे थे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यहां तक कहा था कि यदि एक भी मामला हमें गलत मिला तो हम पूरी एस आई आर की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। आगामी सुनवाई की तिथि पर योगेंद्र यादव ने 16 ऐसे व्यक्तियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जिन्हें मृत बनाकर उनके नाम काट दिए गए थे किंतु वे जीवित थे। इसी आधार पर, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एस आई आर की प्रक्रिया को रद्द कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया गया।

पहली बार इस एस आई आर में नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डाल दी गई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने एस आई आर को मतदाता सूचियां के ‘शुद्धिकरण’ का नाम दिया। तीन माह में एस आई आर की प्रक्रिया को बिहार में जिस प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया गया, उसको देखकर तो केवल यही कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के बजाय इसका ‘अशुद्धिकरण’ कर दिया है।

ड्राफ्ट सूची में हटा दिए गए थे। इसके अलावा लगभग 7 करोड़ अन्य मतदाताओं के लिए आधार को मान्य दस्तावेज माना अथवा नहीं, इस बारे में कोई चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

कई ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूचियां में शामिल हो गए जिनका नाम–पता स्पष्ट नहीं था। उनके नाम किस प्रकार सम्मिलित किए गए इसका भी कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया।

शायद यह इसलिए किया गया कि निर्वाचन आयोग को आशंका हुई कि यदि निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर ही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए, तो कुल मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ से घटकर लगभग 6 करोड़ रह सकती थी। इस कारण अनौपचारिक रूप से, बीएलओ को आपाधापी में सभी नामों को सम्मिलित करने का एक प्रकार से अलिखित आदेश दे दिया गया। इसका परिणाम बीएलओ द्वारा की गई मनमानी के रूप में सामने आया। यह मनमानी, स्पष्ट है कि, सत्ताधारी दल के प्रभाव में ही की गई होगी।

ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि एक ही बी एल ओ द्वारा अनेक व्यक्तियों की तरफ से हस्ताक्षर करके नाम जुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिए गए और ऐसे नाम जुड़ भी गए। अजीत अंबुभ जैसे पत्रकारों ने तो ऐसे कई वीडियो प्रक्रिया के आरंभिक दौर में ही प्रसारित कर दिए थे। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन से पहले ही 99.2% व्यक्तियों ने अपने फॉर्म भर कर दे दिए थे। बाढ़ के दौरान कैसे इतने लोगों के फॉर्म आ गए, यह आश्चर्यजनक है क्योंकि बिहार के लाखों लोग अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु जाते हैं और शिक्षा का प्तर भी देश में सबसे कम है। अतः यह आशंका निर्मूल नहीं है। कि कई ऐसे व्यक्तियों के नाम जुड़ गए हैं जो मतदाता बनने के पात्र नहीं थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 40% व्यक्तियों ने ही 11 में से कोई एक दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक चुनाव आयोग ने उन लोगों की सूची सार्वजनिक नहीं की है जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो गए हैं। नाम काटने के कारण भी नहीं बताए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग 4 लाख ऐसे लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिनके न तो पते स्पष्ट हैं और न ही नाम।

यदि सुप्रीम कोर्ट पहली तिथि पर ही यह स्पष्ट रूप से निर्देश दे देता कि नागरिकता को जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है और 11 दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता सिद्ध नहीं होती है, तो एस आई आर की प्रक्रिया तब ही रद्द कर दी जाती। यह पहली बार हो रहा है कि प्रत्येक उस मतदाता को भी फॉर्म भरकर देने की आवश्यकता पड़ रही है जिसने कई बार मतदान किया है।

बिहार की संभावित 8.28 करोड़ वयस्क जनसंख्या की तुलना में 7.42 करोड़ व्यक्तियों के नाम ही अंतिम मतदाता सूची में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। यह संभव है कि लाखों ऐसे लोगों के नाम छूट गए हों जिनके नाम इसमें होने चाहिए थे और इसी प्रकार से लाखों ऐसे लोगों के नाम जुड़ गए हों जिनके नाम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सारा काम अत्यंत जल्दबाजी में किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया और प्रक्रिया को जारी रखने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट अगली तिथि पर शायद यही कहेगा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं, मतदाता सूची अंतिम हो चुकी है, अतः इसमें अब किसी प्रकार का दखल देना संभव नहीं है। क्या इस प्रकार की स्थिति न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से सही कही जा सकती है? पहले तो आप समय पर निर्णय न करें और बाद में यह कह दें कि अब बहुत विलंब हो चुका है और कुछ नहीं किया जा सकता।

यदि वास्तव में निर्वाचन आयोग ने भारतीय मतदाताओं की नागरिकता जांच के पश्चात उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए हैं, तो क्या भारत सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में हैं उन सबको भारतीय मान लिया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी? क्या जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे एवं क्या उन्हें भारतीय नागरिक को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा? जब तक इस प्रश्न का उत्तर चुनाव आयोग और भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा तब तक एस आई आर के उद्देश्य और इसकी परिणति पर शंका के बादल मंडराते रहेंगे।जनता की यही लगेगा कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के नाम पर की गई कवायद ने मतदाता सूचियां के ‘अशुद्धिकरण’ का ही काम किया है।

निर्वाचन आयोग को अपने हर गलत काम का बचाव करने के स्थान पर एक खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने निर्देशों में परिवर्तन करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से ही इस धारणा को बल मिला कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं, अपितु सत्ताधारी दल के राजनीतिक लाभ के लिए सभी निर्णय ले रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के मूल स्वरूप पर आघात करने वाली होगी क्योंकि देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रथम आवश्यकता मतदाता सूचियों का होना है। देखते हैं, आगामी तिथि पर सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है? लगता तो ऐसा ही है कि योगेंद्र यादव, विभिन्न वकीलों के तर्कों का हथ्र वैयास ही हुआ जैसे “भैस के आगे बीन बजाना”। निर्वाचन आयोग को यदि अपनी पुरानी छवि को पुनः प्राप्त करना है तो उसे खुले मन से चर्चा बैठ तैयार रहना होगा और निष्पक्षता का पूरी तरह सार्वजनिक प्रदर्शन भी करना होगा। यदि ऐसा कर पाया तो निर्वाचन आयोग अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने में सफल हो पाएगा।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अशोक कुमार

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के वित्तीय संकट का विश्लेषण करने के लिए, हमें इसकी आय और व्यय दोनों को समझना होगा, साथ ही उन चुनौतियों पर भी गौर करना होगा जो इसे एक स्थायी वित्तीय संकट की ओर धकेल रही हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की आय के मुख्य स्रोत हैं:-

छात्र शुल्क : यह विश्वविद्यालय की आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि, सरकारी नीतियों के कारण, कुछ वर्गों के छात्रों को फीस में छूट मिलती है, जिससे विश्वविद्यालय की आय प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही राज्य सरकार पर निर्भर रहा है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान स्थिर रहा है या कम हुआ है, जबकि विश्वविद्यालय के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, कुछ आय संपत्ति से ब्याज,

किराये, विभिन्न परीक्षाओं से परीक्षा शुल्क, महाविद्यालयों के संबंधता और अनुसंधान परियोजनाओं से आती है।

विश्वविद्यालय के खर्चों को देखें तो इसमें कई महत्वपूर्ण मदें हैं, जो वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं:-

कर्मचारियों का वेतन और पेंशन : यह विश्वविद्यालय के कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के कारण, यह खर्च लगातार बढ़ रहा है।

अनुसंधान और शिक्षण सामग्री : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अनुसंधान के लिए आधुनिक उपकरण, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पर्याप्त धन की कमी है। विश्वविद्यालय के पुराने भवनों की मरम्मत और नई सुविधाओं के निर्माण के लिए भी बड़ी राशि की आवश्यकता होती है।

वित्तीय दुर्दशा के प्रमुख कारण सरकारी नीतियों का प्रभाव: राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न स्रोतों से मिली आय का 25 प्रतिशत आय काटा जाना और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस का बोझ विश्वविद्यालय पर डालना वित्तीय संकट का एक मुख्य कारण है। यदि यह पैसा विश्वविद्यालय को वापस मिल जाए तो इसकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, जबकि महंगाई और कर्मचारियों के वेतन में

यथार्थ से रूबरू कराता एक दिवा स्वप्न : “अंग्रेजी में लिखी पंक्तिओं ‘फुट प्रिंट्स’ पर आधारित, हिंदी अनुवाद”



प्रो. वीर बहादुर सिंह

किसी व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा

कि वह ईश्वर के साथ मित्रतापूर्वक सैर करने समुद्र के किनारे जा रहा है। दोनों ने बड़ी घनिष्ट वार्तालाप करते काफी दूरी तय कर ली।

भक्त ने प्रभु से पूछा कि-“आप मेरे साथ कहाँ तक चलेंगे?” प्रभु का उत्तर-“जहाँ तक तुझे जाना है वहाँ तक”! भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और चलते-चलते भक्त की गीली रेत में पीछे कभी-कभी देखता जाता वह खुश होता यह देखकर कि हम दोनों के पद चिन्ह रेत में पीछे दिख रहे हैं। भक्त को अहसास हुआ कि अच्छा है प्रभु मेरे साथ हैं।

आगे कुछ दलदल और कंटकापूर्ण स्थान आया जहाँ से सुगमता से पार जाना मुश्किल था, भक्त ने बड़ी कठिनाई से वह कठिन डगर पर की और पीछे मुड़कर देखा तो उसे केवल एक ही पद चिन्ह दिखाई दिए। भक्त बहुत निराश हुआ और सोचा कि मेरे साथी तो कठिन मार्ग आते ही सारे छोड़ गए।

इसी उधेड़बुन में भक्त ने फिर कुछ सुगम दूरी तय की तो उसने देखा कि अब फिर से दो लोगों के पद चिन्ह बन रहे हैं। अतः तो भक्त ने किशायत भरा उलाहना दिया और प्रभु से बोला

उठाना चाहिए?

सामाजिक सुरक्षा का दायित्व पेंशन कर्मचारियों की जीवन भर की सेवा का प्रतिफल है और यह उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।यह सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक पेंशन प्रदान करे।

समानता का सिद्धांत: जब राज्य सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों (जैसे पुलिस, शिक्षा विभाग, आदि) को सीधे पेंशन देती है, तो विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ भी यही नीति लागू होनी चाहिए। पेंशन नीतियों में यह दोहरा मापदंड कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा करता है।

विश्वविद्यालयों पर वित्तीय बोझ कम करना: यदि सरकार पेंशन का भुगतान करती है, तो विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाला एक बड़ा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इससे विश्वविद्यालय अपनी आय का उपयोग छात्रों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में कर सकेंगे, जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया था।

राज्य की प्रतिष्ठा: जब सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी पेंशन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो इससे राज्य की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि राज्य की छवि को भी सुधारेगा।

समाधान की राह: सरकार को

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

—अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर वि.वि.,

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि राज्य की उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

कटीती बंद करनी चाहिए और वंचित वर्ग के छात्रों की फीस सीधे विश्वविद्यालय को देनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के लिए स्व-वित्तपोषण पादयक्रम शुरू करने चाहिए, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। वि.वि.को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, विशेषकर गैर-आवश्यक खर्चों को कम करके।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के समान विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण कदम है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के भी अनुरूप है। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जब तक इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान



125M
CELEBRATING
125 MILLION CUSTOMERS

आया त्योहार हीरो पे सवार

Xtreme 125R | Splendor+ XTEC 2.0



पुराना एक्स-शोरूम

~~₹ 1 00 534~~

शुरूआती
एक्स-शोरूम कीमत

₹ 92 679[#]

GST लाभ ₹ 7 855

सीमित अवधि
ऑफर

पुराना एक्स-शोरूम

~~₹ 80 491~~

शुरूआती
एक्स-शोरूम कीमत

₹ 74 202[#]

GST लाभ ₹ 6 289

इंस्टेंट डिस्काउंट
₹ 10 000[^] तक

HDFC BANK FESTIVE TREATS क्रेडिट कार्ड
Powered by pine labs

कैश बोनस
₹ 3 500^{*}

विशेष कॉर्पोरेट ऑफर्स
₹ 3 200[~] तक

प्रतिदिन EMI
₹ 69^{\$} से शुरू

डाउन पेमेंट
₹ 1 999^{\$} से शुरू



पाएं जीतने का मौका
100% कैशबैक 24 कैरट सोने का सिक्का
और कई अन्य सुनिश्चित लाभ*

Additional offers on:

Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs, Available at select dealerships. *T&C apply, Offer available only on limited stores. *Limited period offer, T&C apply. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. *Ex-showroom price of base variant of Splendor+ and Xtreme125R in Rajasthan.

TOLL FREE
1800 266 0018

अधिकृत डीलर: सवाई माधोपुर: विजय हीरो, 9289922388, टोंक: राजू हीरो, 9289922438, दौसा: अरुण हीरो, 9289922522, गंगापुर सिटी: पालीवाल हीरो, 9289922842, बांदीकुई: झालानी हीरो, 9289922960, देवली: गोयल हीरो, 9289922995, एमोशिएट डीलर: दौसा: शारदा हीरो, नांगल राजावतन, 7428595934, लालसोट: आशीष मोटर्स, 9413326881, करौली: देव मोटर्स, 7428595932, सपोटरा: जिनंदल ऑटोमोबाइल्स, 7428598990, महवा: एम.एस. मोटर्स, 7428595936, निवाई: एस. मोटर्स, 9414273518, नादौती: अवस्थी मोटर्स, 7428598989, हिंडौन सिटी: विष्णु ऑटोमोबाइल्स, 7469294625, वजीरपुर: आशा मोटर्स, 7428595931, सिकंदरा: निरंकार मोटर्स, 7062729676, 6377061716, फेलिकापुरा: मोहित मोटर्स, 9982480849, कैलादेवी: शास्त्री मोटर्स, 9828616188, शिवर: शिव शक्ति मोटर्स, 9414553872, कुरगांव: सैनी मोटर्स, 9828210025, मंडावरी: अभिषेक मोटर्स, 9413453111, सूरौठ: श्री साई मोटर्स, 8114494899 (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) सवाई माधोपुर: विजय हीरो, 9289922388, गंगापुर सिटी: पालीवाल मोटर्स, 9289922842.

1 8 किलो गांजे की तस्करी कर रहे युवक की जमानत याचिका खारिज की हाईकोर्ट ने

गौरतलब है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में 2 0 किलो से कम मात्रा के मादक पदार्थों की तस्करी को वाणिज्यिक के बजाय निजी उपयोग माना जाता है, ऐसे में तस्करों को आसानी से जमानत मिल जाती है

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा 1 8 करोड़ रु. बाजार मूल्य के मादक पदार्थ गांजा “हाईड्रोफोनिक वीड” के साथ पकड़े गए युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि आरोपी युवक करीब 18.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। हालांकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत 20 किलोग्राम से कम की ड्रग्स की मात्रा को कर्मशियल क्वांटिटी (वाणिज्यिक मात्रा) से कम माना जाता है। यानि कि कानून की नजरों में यह मात्रा आरोपी द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए मानी जाती है, ना कि बाजार में बिक्री के लिए। इसी तथ्य को बताते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में

■ परंतु इस बार हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग द्वारा एयरपोर्ट पर 18 किलो “हाईड्रोफोनिक वीड” के साथ पकड़े गए तस्कर की जमानत यह कहते हुए खारिज की है कि, “तस्करों ने एक नया तरीका अपना लिया है कि वह ज्यादा नशीले मादक पदार्थों की 20 किलो से कम मात्रा में तस्करी पढ़े-लिखे नौजवानों से करवाते हैं, ताकि उन्हें आसानी से जमानत मिल सके।”

■ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “वह यह नहीं चाहती कि वह ड्रग्स तस्करी के ऐसे प्रकरणों में जमानत याचिका स्वीकार करके नौजवान युवकों के लिए एक गलत मिशाल तय करे, जो कि उन्हें अपराध की दुनिया की ओर बढ़ाता हो”

कहा गया कि, आरोपी करण मेहरा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उस पर कोई भी अपराधिक केस नहीं है। इसलिए अदालत जमानत याचिका स्वीकार कर आरोपी की रिहाई के आदेश दे। वहीं केन्द्र सरकार की ओर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्रशेखर सिन्हा ने अदालत को बताया कि, इस मामले में आरोपी करण मेहरा गांजे की विशिष्ट प्रजाति “हाईड्रोफोनिक

वीड” को तस्करी करके ला रहा था, जिसमें टी.एच.सी. की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस गांजे को विशिष्ट जगहों पर ही उगाया जाता है। उन्होंने अदालत को कहा कि, यह गांजा बहुत ज्यादा नशीला और व्यसनकारी होता है, इस वजह से इस गांजे का मूल्य भी बाजार में बहुत ज्यादा है। बाजार में सामान्य गांजे की कीमत प्रति किलो 5 से 10 लाख रु. तक की मानी जाती

करवाते हैं, ताकि युवकों को आसानी से जमानत मिल जाए।

अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद कहा कि, उन्हें हैरानी है कि किस तरह से अपराधिक तस्कर गिरोह कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों को महंगी विदेश यात्राएं और पैसों का लालच देकर उन्हें तस्करी के गत में धकेल रहे हैं और ऐसे युवकों को अगर आसनी से जमानत मिल जाए तो यह अन्य युवकों के लिए भी अपराध का रास्ता चुनने का प्रोत्साहन हो जाएगा।

अदालत ने कहा कि, वह यह नहीं चाहती कि वह आरोपी करण मेहरा की जमानत याचिका स्वीकार करके नौजवान युवकों के लिए एक गलत मिशाल तय करे। इसलिए न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

वरिष्ठ नागरिकों को कराया जयपुर भ्रमण

जयपुर। टाईम बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 75 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को निःशुल्क जयपुर भ्रमण कराया गया। 35 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को डबल डेकर बस द्वारा जयपुर के पर्यटन स्थलो की सैर कराई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बिरला मंदिर से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया । टाईम बैंक ऑफ इंडिया देश में एक अनूठा विचार लेकर आया है, जहां एकाकी बुजुर्गों को निःशुल्क रूप से मानवीय सहायता प्रदान कर उनकी देखभाल की जाती है। सेवा के समय की बैंक की पासबुक में चंटों के रूप में प्रविष्टि भी की जाती है। सदस्य इस जमा समय का उपयोग भविष्य में कर सकते है। उनका विभाग वरिष्ठ नागरिकों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है। इस अवसर पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कुछ अति वरिष्ठ नागरिकों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लिया। गहलोत ने बुजुर्गों की सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर टाईम बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त पुरस्कार के लिए बधाई दी। बस में भ्रमणार्थियों की सहायता के लिए बैंक के युवा सदस्य आकाश शर्मा, पूजा शर्मा एवं अंजू पीयूष साथ रहे।

तकनीकी नवाचारों से मिलेगी शहरी विकास को रफ्तार : रवि जैन

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव ने दिया क्षमता संवर्धन कार्यशाला में नवनियुक्त अधिकारियों को व्याख्यान

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और मंत्री झावर सिंह खर्ग के निदेशन में स्वायत्त शासन विभाग जनसेवा के नये आयाम स्थापित कर रहा है।

एमएनआईटी के अमरूत सेंट्र में नवनियुक्त अधिशासी और राजस्व अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शासन सचिव रवि जैन ने इस कार्यशाला में सोच्चार को अधिकारियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया । जैन ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अभ्यास से ही वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। उन्होंने कहा की क्षेत्र अधिकारी के रूप में, आपका कार्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की प्रगति और समृद्धि की नींव को



स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने एमएनआईटी में नवनियुक्त अधिशासी और राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया।

मजबूत करना है। आज के तेजी से बदलते समय में, हमें कुछ नया और अलग सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की तकनीकी नवाचारों से

है और भविष्य की क्या कार्य योजना है। जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश गिराज प्रसाद व अन्य की याचिका पर दिया।याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक व विनोद सिंघल ने बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के मंडावारा रोड के निवासी है। यहां मुख्य रोड पर करीब डेढ़ साल से सीवरज व वर्षा शक्ति घरों के गंदे पानी का जमावडा हो रहा है। इस रोड से 25 कॉलोनिमें और कई गांव के लिए रास्ते जाते हैं। इन रास्तों पर रोजाना हजारों वाहन

जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश गिराज प्रसाद व अन्य की याचिका पर दिया।याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक व विनोद सिंघल ने बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के मंडावारा रोड के निवासी है। यहां मुख्य रोड पर करीब डेढ़ साल से सीवरज व वर्षा शक्ति घरों के गंदे पानी का जमावडा हो रहा है। इस रोड से 25 कॉलोनिमें और कई गांव के लिए रास्ते जाते हैं। इन रास्तों पर रोजाना हजारों वाहन

व पैदल यात्री निकलते हैं। आए दिन गंदे पानी में लोग गिर जाते हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाली भी नहीं है। इस बारे में स्थानीय जिला प्रशासन व नगर परिषद को कई बार प्रतिवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गंदे पानी की निकासी के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। जिस पर सुमवाई करते हुए एकलपट्टी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए शपथ पत्र पेश कर आगामी कार्य योजना पेश करने को कहा है।

विधियों को सीखें।हमे परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए उकृष्टता की ओर बढ़ना है।

जैन ने व्याहवारिक ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए सभी नयनियुक्त अधिकारियों को अपना आचरण सौम्य और संवेदनशील बनाए रखने का आह्वान किया । उल्लेखनीय है कि 111 प्रशिक्षणार्थियों को इस 45 दिवसीय कार्यशाला में तकनीकी विषयों एवं निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न तकनीकी नवाचारों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न सत्र होंगे जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जायेगा। इस उद्घाटन सत्र में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर सहित अन्य अधिकारी, एमएनआईटी के प्रोफेसर एवं सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे ।

विद्याश्रम स्कूल में री-यूनियन समारोह हुआ

जयपुर। विद्याश्रम स्कूल, जयपुर के 2004 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने स्कूल के 21 साल पूरे होने के अवसर पर एक यादगार रियूनियन समारोह आयोजित किया।

यह आयोजन बैच के सहपाठियों द्वारा स्वयं आयोजित किया गया और जयपुर के प्रसिद्ध क्लेबोर्न रेस्तरां में संपन्न हुआ।

इस रियूनियन समारोह में देश भर से पूर्व छात्र अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए पहुंचे। कई सहपाठी वर्षों बाद एक-दूसरे से मिले, जिससे समारोह में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। सभी ने अपने स्कूल के दिनों की पुरानी यादों को ताजा किया और पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो उठे।

विचार विमर्श हुआ।

उल्लेखनीय है इस दल में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर.चौधरी, पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, कृषि विभाग के शासन सचिव राजन विशाल के साथ साथ कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों के 9 अधिकारी तथा 38 किसान और पशुपालक भी शामिल हैं।

दल का नेतृत्व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत कर रहे हैं। दल के सदस्यों ने बताया कि यह राजदूत मनीष प्रभात के साथ मुलाकात अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक रही। डेनमार्क की उन्नत तकनीकों और नीतिगत नवाचारों का अनुभव राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा और हमारा यह अनुभव कार्य में नई योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

भारतीय मजदूर संघ की बैठक

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ, जयपुर जिला इकाई की कार्यसमिति बैठक सोमवार को संघ कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री रंजीत सिंह गुर्जर, अध्यक्ष – भारतीय मजदूर संघ, जयपुर जिला इकाई ने की। बैठक में आगामी प्रदेश स्तरीय श्रमिक हुंकार रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई, जो 26 दिसंबर को जयपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पदाधिकारी व सदस्य विभिन्न संगठनों से जुड़कर अधिकतम संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि संगठन की एकता और शक्ति का प्रदर्शन हो सके। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रचारक जयंतीलाल और प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कार्यसमिति को मार्गदर्शन प्रदान किया।

विधानसभा पहुंचने पर देवनानी का अभिनंदन

बारबाडोस सम्मेलन और यू.के. अध्ययन यात्रा से लौटे हैं देवनानी

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का सोमवार को यहां विधान सभा पहुंचने पर विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभिनंदन किया। देवनानी बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेकर और संसदीय परम्पराओं का यू.के. में अध्ययन यात्रा के बाद रविवार को वापस लौटे हैं।

देवनानी का विधान सभा कर्मियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर, साफा, फूल माला और दुपट्टा पहनाकर और शॉल ओढाकर अभिनंदन किया। देवनानी ने सभी विधान सभा कर्मियों के हाल-चाल पूछे। देवनानी के साथ इस यात्रा में प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी गये थे। उल्लेखनीय है कि बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में देवनानी ने राजस्थान के प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में राउंड टेबल परिचर्चा में लोकतंत्र को समर्थन देने के लिए हमारी संस्थानों का सुदृढीकरण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इसका खतरा-

हाईकोर्ट ने खारिज की पेपरलीक के आरोपियों की जमानत याचिका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के पेपरलीक के आरोपी पुखराज, अनिल कुमार, अरूण शर्मा और भूपेन्द्र सारण की जमानत याचिका खारिज की है। इस मामले में पेपर बेचकर पैसों की हेराफेरी करने के मामले में ई.डी. द्वारा जांच की जा रही है।

अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि, उन पर मनी लॉडिंग (पैसों की हेराफेरी) के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जांच तबित है। सभी लोग काफी समय से जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए।

इस मामले में ई.डी. की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि, सभी अभियुक्तों पर अलग-अलग पेपरलीक करने के आरोप हैं। आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ ई.डी. ने शिकायत दर्ज की थी, आरोप है कि अनिल ने पेपरलीक के पैसों से प्रॉपर्टी की खरीद की। भूपेन्द्र सारण, मुख्य आरोपी है, जिसने पेपरलीक का पूरा गिरोह चलाया है। आरोपी अरूण शर्मा वर्ष 2019 में फर्जी रेलवे भर्ती परीक्षा में भी मुख्य आरोपी है, इस पर 2.5 करोड़ रु. हड़पने के मामले सामने आये हैं। वहीं आरोपी पुखराज और उसके साथ सुरेश व पीराराम को उच्च माध्यमिक भर्ती

परीक्षा में ईडी ने एक साथ पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा था। ई.डी. की ओर से बताया गया कि, इन आरोपियों पर आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा से सीधे पेपर खरीदने के आरोप हैं। ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जाए।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, सभी आरोपियों पर काफी गंभीर आरोप हैं, अभी तक जितने भी तथ्य कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं, उन्हें देखते हुए जमानत याचिका स्वीकार करना ठीक नहीं है। इस टिप्पणी के साथ न्यायाधीश अशोक जैन ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

सहकार दीपोत्सव मेले में 5 5 प्रतिशत तक छूट पर मिलेंगे शिवकाशी के ग्रीन पटाखे

सहकारिता मंत्री ने किया ‘सहकार दीपोत्सव मेला-2025 ’ का विधिवत शुभारम्भ

जयपुर (कांस)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) द्वारा आयोजित किए जा रहे

■ जयपुर में 13 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होगा मेला, यहां ग्रीन पटाखे और त्योंहारी सामग्री भी मिलेगी

‘सहकार दीपोत्सव मेला-2025’ का गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 19 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। यहां शिवकाशी (तमिलनाडू) के ग्रीन पटाखे, 55 प्रतिशत तक डिस्काउंट पर मिलेंगे। आमजन के लिए यहां गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे और अन्य त्योंहारी सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध कराई गई है।

मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। मेले में एमएमटीसी के चांदी के सिक्के भी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को



सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सोमवार को दीपोत्सव मेले का उद्घाटन करने के बाद स्टॉल्स का अवलोकन किया।

उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मेले के प्रति लोगों का रिसर्प्स देखते हुए उम्मीद है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री होगी। सहकारिता मंत्री ने मेले में लग्गी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर बिक्री के लिए लाये गए उत्पादों तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मेले में सुरक्षा एवं अग्नशमन संबंधी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहकार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी प्लांवर, डिजाइनदार कैडल्स,

बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, सुखे मेवे के उद्धार पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है। साथ ही, मिलेट उत्पादों का आउटलेट भी दीपोत्सव मेले में लगाया गया है। इस अवसर पर विधायक हमीर सिंह भायल, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल, कॉन्फेड की प्रबंध निदेशक शिल्पी पांडे सहित सहकारिता विभाग व उपभोक्ता संघ के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड’ से नवाजा

जयपुर। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित भव्य समारोह में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाजसेवा, लोककल्याण तथा राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

यह सम्मान राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। डॉ. चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने, वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण तथा स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए कई अभिनत पहलें की हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष



राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।

अमरा राम जांगिड ने बताया कि इस अवसर पर दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे वासु श्रॉफ, तथा बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रवासी सम्मान अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया।आरबीपीजी अध्यक्ष हरिकिशन रांकावरत ने कहा कि डॉ. अरुण चतुर्वेदी को समाज कल्याण, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में उनके समर्पण के

लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में दुबई में भारत के कॉन्सुल जनरल सतीश शिवन, आरबीपीजी चेयरमैन लालाराम, बोर्ड डायरेक्टर डॉ. केसर कोठारी, उपाध्यक्ष डॉ. रोमित पुरोहित सहित संगठन के सभी ट्रस्टी एवं लगभग 1200 प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उद्योगपति परिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्थान मूल के प्रसिद्ध संगीतकार शारिर-तोशी की प्रस्तुति ने समां बाँध दिया।

पेट्रोल पंप पर सेल्समैन ने की मारपीट

जयपुर। बहपुरी थाना इलाके में बाइक में पेट्रोल भरवाने आए एक युवक और सेल्समैन की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन ने बाइक सवार युवक से मारपीट शुरू कर दी। तभी कुछ लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक को सीसीटीवी फुटेज समेत थाने बुलवाया। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की ओर से किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है।पुलिस उपायुक्त जयपुर उस्तर करन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर 11 अक्टूबर का एक वीडियो वायरल हो रहा था।

जिसमें पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन एक युवक से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के सत्यापन के बाद पेट्रोल पंप संचालक को सीसीटीवी फुटेज सहित थाने बुलवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के सत्यापन के बाद जांच की जाएगी।

ग्रामीण बैंक प्रबंधक के लिये 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार

आरोपी प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेटाली जिला डूंगरपुर को भी डिटैन किया

डूंगरपुर, (निर्स)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर द्वारा सोमवार को कार्रवाई करते हुये आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेटाली जिला डूंगरपुर के लिए दलाल भूपेन्द्र कुमार परमार बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर को परिवारी से 45 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एबसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को 7 अक्टूबर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवारी व उसके भाई एवं मां के नाम से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेटाली से कृषि भूमि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए अलग-अलग कुल 11 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था,



एसीबी की टीम ने दलाल को गिरफ्तार कर प्रबंधक को डिटैन किया। (गोले में)

जो ऋण पास कराने के लिए परिवारी बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो परिवारी के ऋण के 2 लाख रुपये दिये व 2 लाख रुपये बाकी रखे व कहा कि तुम्हारे परिवार वालों के

मैने जो 11 लाख रुपये का ऋण पास किया है उसके लिए मैं पचास हजार रुपये लूंगा, जो 50 हजार रुपये लेने के लिए मेरे मिलने वाले व्यक्ति का आपके पास फोन आयेगा उसे दे देना।

बैंक मैनेजर द्वारा परिवारी का ऋण स्वीकृत करने की एवज में 50 हजार रुपये कि रिश्त की मांग की जा रही है। जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के प्रहलाद सिंह कृष्णिया, उप

■ **किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण के एवज में 50 हजार रिश्वत राशि मांगी थी**

महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में एसीबी डूंगरपुर के रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में राजेन्द्रसिंह, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह हाल प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेटाली जिला डूंगरपुर के लिए दलाल भूपेन्द्र कुमार हाल बैंक मित्र मुख्य को परिवारी से अपनी मांग अनुसार 45 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्त राशि बरामद की गई व आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेटाली जिला डूंगरपुर को भी डिटैन कर लिया है। एसीबी द्वारा आरोपियों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्रवाई जारी है।

अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय सचिन पायलट पर छोड़ा, प्रस्ताव पास

अजमेर उत्तर एवं दक्षिण विधानसभा के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने बैठक में अजमेर से सांसद रहे सचिन पायलट में विश्वास जताया

अजमेर, (कांस)। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर के सानिध्य में अजमेर दक्षिण एवं उत्तर विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की बैठक जयपुर रोड स्थित एक वाटिका में आयोजित हुई। बैठक में मौजूद समस्त कांग्रेस जनों ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और अजमेर लोकसभा से सांसद रह चुके सचिन पायलट अजमेर शहर कांग्रेस

■ **कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर के सानिध्य में नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई**

अध्यक्ष पद के लिए जो भी नाम प्रस्तावित करेंगे, वह हम सबके लिए सर्व मान्य होगा। जिस पर बैठक में मौजूद सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने हाथ खड़े कर एक सूर में पायलट के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया और सचिन पायलट जिंदाबाद के

नारों से बैठक स्थल गुंजायमान हो गया। बैठक में तंवर का पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, दक्षिण विधानसभा से पीसीसी सदस्य हेमंत भाटी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तंवर ने बैठक को संबोधित करते

हुए कहा कि एआईसीसी का यह अभियान कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित, सक्रिय और जनसरोकारों से जुड़ा बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अजमेर जिले में इस अभियान से पार्टी को स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और आंतरिक संवाद मजबूत करने की दिशा में बल मिलेगा। अभियान का मकसद जिला कांग्रेस कमेटियों से लेकर बुध स्तर तक पार्टी को सक्रिय करना और संगठन को जवाबदेही के नए पैमाने पर खड़ा करना है।

सरकारी स्कूलों में अब कोचिंग जैसे रिवीजन मॉडल पर जोर रहेगा

बीकानेर, (निर्स)। कोचिंग सेंटरों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी रिवीजन पर जोर रहेगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्कूलों में 15 नवंबर तक पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाए, ताकि दिसंबर में होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले रिवीजन कराया जा सके।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमित अध्ययन और पुनरावृत्ति से विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होता है। रिवीजन केवल याद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समझ को गहरा करने और ज्ञान को लंबे समय तक बनाए रखने का प्रभावी तरीका है। रिवीजन के दौरान विद्यार्थी अपने कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा के समय तनाव व घबराहट कम

■ **शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्कूलों में 15 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाए**

■ **पाठ्यक्रम पूरा होने पर दिसंबर में होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले रिवीजन कराया जा सके**

होती है। आदेश में कहा गया है कि जब विद्यार्थी किसी विषय की बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो वह जानकारी अल्पकालिक स्मृति से निकलकर दीर्घकालिक स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज हो जाती है।

इससे परीक्षा के समय उत्तर तेजी और सटीकता से दिए जा सकते हैं। सभी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 नवंबर तक अपने-अपने विषयों का पाठ्यक्रम पूरा करें, ताकि इसके बाद केवल रिवीजन सत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। रिवीजन के

दौरान कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़े और कमजोर विषयों में भी वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि गत शिक्षा सत्र में राज्य स्तरीय समान परीक्षा से संबंधित जो नीलपत्र और दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, वे इस सत्र में भी यथावत रहेंगे। सभी विद्यालयों को इन निर्देशों के अनुरूप तैयारी करने और परीक्षा पूर्व रिवीजन की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राजगढ़, (निर्स)। पालिका प्रशासन की ओर से सेवा शिविर में पट्टा बनाने के नाम पर परिवारी से 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते रामहेत बैरवा राजस्व निरीक्षक को एसीबी के एएसपी महेंद्र मीणा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्रकरण के अनुसार परिवारी की और से कस्बे के रेवारपुरा राजगढ़ ने 242 वर्ग गज प्लाट का पट्टा बनाने के लिए 3 अक्टूबर को 75978 की राशि जमा कराई। इसके बाद भी पट्टा नहीं बनाने पर 9 अक्टूबर को परिवारी रामहेत बाबू से मिला, तो उसने पत्नी के नाम पट्टा जारी करने एवं भूमि का कन्वेन्शन आदेश जारी करने के नाम पर 15 हजार की रिश्वत की मांग की। इस पर आरोपी की ओर से तीन हजार रुपए 10 अक्टूबर को रिश्वत माग कर वसूली की।



आरोपी रामहेत बैरवा राजस्व निरीक्षक।

शिकायत का सत्यापन होने के बाद आरोपी की ओर से पट्टे के नाम पर दस हजार रुपए एवं कन्वेन्शन के नाम पर दो

■ **पट्टा बनाने के नाम पर परिवारी से 12 हजार रुपए की रिश्वत ली**

हजार रुपये सहित 12 हजार रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया। इस पर ट्रेप की कार्रवाई का आयाजित किया गया, जिसमें आरोपी रामहेत बैरवा राजस्व निरीक्षक भूमि शाखा नगर पालिका राजगढ़ को बाई जेब टी-शर्ट से परिवारी की ओर से दी गई रिश्वत की राशि बरामद की। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर एसीबी चौकी आरोप प्रथम के राजेश सिंह महानिरीक्षक के सुपरविजन में कार्रवाई से शिविर में हड़कंप मच गया।

ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत

पावटा, (निर्स)। विराटनगर थाना क्षेत्र के पालडी तिराहे के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई।

मेड चौकी प्रभारी विनोद चेची ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि विकास गुर्जर (20) सुबह अपने घर बीछावाला से पालडी तिराहे की तरफ कोचिंग के लिए आ रहा था तभी साइड में आ रहे ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार विकास गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद विक्रम गुर्जर ने बताया कि बाइक सवार अपनी साइड से सही तरह से आ रहा था। साइड से ओवरलोड ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने लापरवाही से रोड पर चढ़ाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बाइक सवार युवक का बैग दूर जाकर खेतों में गिर गया और युवक ट्रैक्टर से थोड़ी दूर तक घसीटा हुआ चला गया और युवक की ट्रैक्टर के टायर नीचे आने से मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही युवक के परिजनों को मिली तो मेड सीएचसी में कोहराम मच गया। मृतक दो भाई दो बहनें हैं। ग्रामीण भैरुराम गुर्जर व योगेश जांगिड़ ने बताया कि मृतक विकास गुर्जर सबसे बड़ा था। मृतक विकास गुर्जर के परिवार



मृतक फाइल फोटो

की स्थिति बहुत ही दयनीय है। परिवार कच्चे घर में अपना जीवन-यापन करता है। पुलिस ने घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया साथ मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

पिकअप की टक्कर से युवक की मौत

डूंगरपुर, (निर्स)। दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली के पास रविवार शाम बाइक सवार युवक को पिकअप से टक्कर

■ **युवक सुबह अपने घर बीछावाला से पालडी तिराहे की तरफ कोचिंग के लिए आ रहा था, रास्ते में हादसा हुआ**

लगने के बाद मौत हो गई। युवक पेट्रोल पंप की ओर बाइक से आ रहा था। दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार, प्रहलाद सिंह पुत्र पदमसिंह शक्तावत ने रिपोर्ट में बताया गया कि उनके जीजा मदनसिंह पुत्र फतेहसिंह चौहान निवासी टेकला बाइक लेकर गांव जा रहे थे। पुनाली के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में मदनसिंह के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें 108 एंबुलेंस से डूंगरपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दोवड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोचरी में रखवाया। सोमवार को पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को खिलाफ तेज रफ्तार से वाहलर चलाकर दुर्घटना कारित करने का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

खेत में बने पॉण्ड में डूबने से युवक की मौत

निवाई, (निर्स)। सोमवार की सुबह गांव जयसिंहपुरा के एक खेत में बने हुए फॉर्म पॉण्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।

थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि धर्मराज (20) पुत्र रामावतार रंगर निवासी जामडौली हाल सौरभ विहार कॉलोनी जयसिंहपुरा सोमवार को गांव जयसिंहपुरा में एक खेत पर बने फॉर्म पॉण्ड में नहाने गया था। नहाते समय वह डूब गया। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को बुलवाया। टीम द्वारा काफी मशकतत के बाद देर शाम को युवक के शव को फॉर्म पॉण्ड में से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को उप जिला अस्पताल की मोचरी में रखवाया है। उन्होंने बताया कि मृतक धर्मराज सोमवार को सुबह बकरियां चराने गया था, जो दोपहर बाद भी घर नहीं लौटा तो उसके परिजन उसको ढूँढते हुए खेतों की तरह पहुंचे। गांव जयसिंहपुरा में स्थित फार्म पॉड के किनारे उसके कपड़े व मोबाइल मिले। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि मृतक धर्मराज के दो छोटे भाई व तीन छोटी बहनें हैं। धर्मराज को गांव और महिला को एक होटल में ले गया। होटल की छत पर जाकर रविंद्र ने जबर्न महिला को बिपर पिलाई और कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करने

■ **आरोप है कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की**

की कोशिश करने लगा। उसके कुछ दिन बाद रविंद्र की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में E1/EWS/D-1 श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रायत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से कुल 03 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा वेबसाइट एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in>, [www.urban.raajasthan.gov.in/utibharatpur](http://urban.raajasthan.gov.in/utibharatpur) एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal का अवलोकन करें।

UBN विवरण :- **WAQ2526WSOB00241, WAQ2526WLOB00242, 00243**

राज.संवाद/सी/25/12009

अधिकांशी अधिकृत (विद्युत)

रेप मामले में कार्रवाई नहीं होने से महिला टंकी पर चढ़ी

भरतपुर, (निर्स)। रेप के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज एक महिला भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब एक घंटे तक पुलिस ने महिला से समझाइश की, जिसके बाद महिला को टंकी से नीचे उतारा गया। उसके बाद पुलिस की टीम अरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने से रवाना हुई।

दो महीने से पुलिस महिला को कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। 21 अगस्त को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह मथुरा गेट थाना इलाके की रहने वाली है। रविंद्र मीणा नाम का व्यक्ति उससे दो साल रेप करता आ रहा है। उसके खिलाफ महिला ने मथुरा गेट थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। समाज के लोगों द्वारा समझाने के बाद महिला ने मुकदमे में राजीनामा कर लिया गया। उसके बाद भी रविंद्र महिला को परेशान कर रहा है। 21 अगस्त 2025 को रविंद्र ने महिला को फोन किया और कहा कि मुझे मिलना है। जब महिला ने रविंद्र से मिलने को मना कर दिया तो, रविंद्र ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। उसी दिन जब महिला घर के जरूरी काम से बाजार जा रही थी तो, रविंद्र ने उसे रास्ते में रोका और महिला को एक होटल में ले गया। होटल की छत पर जाकर रविंद्र ने जबर्न महिला को बिपर पिलाई और कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करने

के लिए थाने से रवाना की गई।

कार और ट्रक की टक्कर में दो जनों की मौत, तीन घायल

एक कार चालक की ड्राइविंग सीट पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई

■ **प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी यात्री लूणकरणसर क्षेत्र के निवासी थे और बाइमेर की ओर जा रहे थे**

जोरदार थी कि कार में तत्काल आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार चालक ड्राइविंग सीट पर ही जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही नापसर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। पुलिस ने घायलों को तत्काल बीकानेर के पीबीएम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, अटिंगा कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं। इनमें जमना, ज्योति और संतोष के नाम सामने आए हैं। संतोष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि जमना और ज्योति सहित अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। एक अन्य घायल रामचंद्र और दिनेश भी गंभीर हालत हैं। कार चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वह हादसे में पूरी तरह जल गया।

टोंक में विभिन्न प्रकरणों में दो आरोपी को गिरफ्तार : थानाधिकारी मेहनवास के द्वारा गटित टीम ने नाकाबंदी के दौरान उस्मानपुरा कट सोनवा टोल प्लाजा के पास एनएच 52 पर एक संदिग्ध से पूछताछ के बाद डिटैन कर संतोषप्रद जवाब नही देने पर एवं मादक पदार्थ में लिप्त पाये जाने पर आरोपी मेहेन्द्र गुर्जर पुत्र रमेश चन्द गुर्जर निवासी हमीदपुरा थाना बरोनी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपी की तलाशी लेने पर पैट की जेब से 2.5 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्कैफ मिलने पर जब कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। वहीं मेहनवास पुलिस टीम ने अरनिवानील से करीमपुरा जाने वाली रोड पर अवैध टोपीदार एकनाली बर्दूक ले जाते पाये जाने पर आरोपी केसरा मोन्या पुत्र भूरा मोन्या को गिरफ्तार कर बर्दूक जब्त की।

Government of Rajasthan Office of the DSO CHURU Email:-dsolood-chu-rj@nic.in Phone No.: 01562-250927 F(P)/PDS/Tender/2025-26/5978 Date:-07/10/2025	
NOTICE INVITING BID e-Bids for selection of Handling and Transportation of Food grains Under PDS from FCI Depots in District Churu were invited from interested bidders up to 27.10.2025Till 6.00PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.raajasthan.gov.in or http://sppp.raaj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement is Rupees 3.9 Crore for One year. NIB No. :- CCH2526A0010 UBN No. :- CCH2526SL0B00017	
ANSHU TIWARI District Supply Officer Churu	
DIPRC/14978/2025	
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, P.W.D., CIRCLE-JHALAWAR Room No.158, Ground Floor (Public Works Department), Mini Secretariat, Jhalawar E-mail: piu.jhalawar@rediffmail.com msjewar.pwd@rajasthan.gov.in, Phone No.: 07432-233336 S. No. :- 817 NIT No. 09/2025-26 Date: 03.10.2025	
Notice Inviting Bid NIB No. PWD202526A3668 Bids for "Construction of Non-patchable & Missing link Roads in Dist. Jhalawar in compliance with point number 17 of the Budget Announcement for the year 2025-26" are invited from interested bidders upto 6.00 PM, Dated 30.10.2025 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.raajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the Rajasthan http://pwd.raajasthan.gov.in website. The approximate value of the procurement is Rs. 18.18 Lacs. and UBN No.-PWD2526WSOB13818	
(Mukesh Chand Meena) Superintending Engineer Public Works Department Circle-Jhalawar	
DIPRC/14903/2025	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड कोटाड, उदयपुर क्रमांक-630 NIT No. 12/2025-26 Date:-03.10.2025	
Notice Inviting Bid Bids for "Various Road's Construction, Renewal, Strengthening Works in various schemes in District Udaipur (Raj.) are invited from interested bidders upto 6.00 PM, Dated 20.10.2025 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.raajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the Rajasthan http://pwd.raajasthan.gov.in website. The approximate value of the procurement is Rs. 143.68 Lacs. NIB:- PWD2526A3695 UBN No. 1:-PWD2526WSOB13909 UBN No. 2:-PWD2526WSOB13911	
(Vijay Kumar Meena) Executive Engineer Public Works Department Division Kotra Udaipur	
DIPRC/14879/2025	

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण क्रमांक:- एफ.10 / 2025-26 / 5239 दिनांक:- 07.10.2025	
:: अल्पकालीन ई-निविदा सूचना :: (UBN No. DLB2526WSOB20996) नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से विभिन्न सिविल कार्यों हेतु ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि http://eproc.raajasthan.gov.in, www.sppp.raajasthan.gov.in एवं https://lsr.raajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है। महापौर आयुक्त नगर निगम जोधपुर-दक्षिण नगर निगम जोधपुर-दक्षिण राज.संवाद / सी / 25 / 12028	

बीकानेर नगर निगम नगर निगम मा. बीकानेर (राजस्थान) फ़ैस :- 0151-2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-Mail Address :- nagarinagam@bikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikaner.nic.in क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 17092 दिनांक 08.10.2025	
ई- निविदा-सूचना सं 132/ 2025-26 नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यों (कुल 01 कार्यों) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "रेप्रे", "रेप्रे" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विवरण वेब साईट www.bikaner.nic.in Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा की कुल लागत 14.43 लाख UBN Number DLB2526WSOB21171 राज.संवाद / सी / 25 / 12032	
आयुक्त नगर निगम, बीकानेर	

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर क्रमांक :- लेखा/म.वि.प्र./2025-26/14138 दिनांक :- 09/10/2025	
ऑनलाइन निविदा सूचना सं. 20/2025-26 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में E1/EWS/D-1 श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रायत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से कुल 03 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा वेबसाइट एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in, www.urban.raajasthan.gov.in/utibharatpur एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.raajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवलोकन करें। UBN विवरण :- WAQ2526WSOB00241, WAQ2526WLOB00242, 00243 राज.संवाद/सी/25/12009	
अधिकांशी अधिकृत (विद्युत)	

कार्यालय नगरपरिषद, राजसमन्द	
जिला परिषद रोड, राजनगर	
टैलफोन नं. 02952-220034, फ़ोन नं. 02952-221233, ई-मेल rajsamand@rajaspalika@gmail.com क्रमांक :- एफ/नगर/ई/ई निविदा/20/2025-26/5515 दिनांक :- 09.10.2025	
ई-निविदा सूचना संख्या 20/2025-26	
नगर परिषद राजसमन्द द्वारा विकास कार्यों हेतु समस्त विभागों में पंजीकृत संवेदकों, कम्पनी, संयुक्त/संस्थाओं से ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन तकनीकी व वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in , www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।	
निविदा कार्यक्रम	तिथि व समय
कार्यों की सूचना	
कार्यों की अनुमानित लागत	125.10 लाख
निविदा अपलोड की तिथि	09.10.2025 06:00 PM
निविदा डाउनलोडिंग प्रारम्भ तिथि	10.10.2025 09:00 PM
ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	20.10.2025 06:00 PM
भौतिक रूप से दरतालाज जमा करने की तिथि	21.10.2025 01:00 PM
ऑनलाइन निविदा खोलने की तिथि	21.10.2025 04:00 PM
ऑनलाइन निविदा हेतु वेबसाइट	http://eproc.raajasthan.gov.in
दोष निवारण अर्चो	नियमानुसार
UBN NO-	DLB2526WSOB21094, 21095, 21096, 21097, 21098 & 21099
राज.संवाद / सी / 25 / 11984	समाप्तति आयुक्त

‘इतने कम समय में 7 लाख करोड़ रूपए के एमओयू ज़मीन पर उतरे, बहुत बड़ी उपलब्धि है’

जयपुर, 13 अक्टूबर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत बेहतरीन काम किया है। समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से तीन लाख करोड़ के एमओयू का कार्य पूर्व में धरातल पर शुरू हो चुका है। वहीं, आज लगभग चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू से जुड़ी योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। शाह ने कहा कि हम जो कहते हैं, वो करते हैं। मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में इतने कम समय में 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू जमीन पर उतरे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जे ई सी सी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ‘नव विधान : न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन किया तथा पूरी प्रक्रिया का लाइव डैमो देखा।

अमित शाह ने सीतापुरा स्थित जयपुर एजोविशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदेश के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपये एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

गृह मंत्री अमित शाह ने 4 लाख करोड़ रूपए के एमओयू का भूमि पूजन किया व कानून प्रदर्शनी का उद्घाटन किया



केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के क्रम में, पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को इन नए कानूनों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, ये तीन नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्रांतिकारी

कदम हैं। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा

ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन नए आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत नियम और अधिसूचना जारी करके इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। ये नए कानून केवल दण्ड देने के लिए नहीं, बल्कि समाज को राह दिखाने का माध्यम बनेंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया

■ केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राईजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के अंतर्गत बेहतरीन कार्य के लिए मुख्यमंत्री व उनकी टीम की प्रशंसा की।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि नये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक तंत्र को व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अमेरिका व चीन में ट्रेड वॉर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चीन के कब्जे में थे, अपनी जगह बना सकता है। भारत के कई उद्योग अभी से इस अवसर को समझ रहे हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, को अमेरिकी ऑर्डरों में तेज़ वृद्धि देखने को मिल सकती है, खासकर उन श्रेणियों में, जहाँ अब तक चीन का दबदबा था।

खिलौने और जूते-चप्पल बनाने वाले उद्योगों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि सस्ते माल की श्रेणी में चीन की बढ़त अब कमजोर होती दिख रही है। भारतीय निर्यातक मनु गुप्ता ने बताया कि “टारगेट” जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेता पहले से ही नई उत्पाद श्रृंखलाओं के लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण, जैसे वाॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और छोटे घरेलू सामान बनाने वाले उद्योगों को भी नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी इम्पोर्टर अब चीनी फ़ैक्ट्रियों के विकल्प तलाश रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी, जैसे-जैसे चीन दुर्लभ धातुओं और संबंधित तकनीकों के निर्यात को सीमित कर रहा है, भारतीय

सौर पैनल और पवन टरबाइन पुर्जें बनाने वाली कंपनियाँ भी अपनी जगह मजबूत कर सकती हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह गुणवत्ता, स्थिरता और समय पर आपूर्ति के मानकों से कोई समझौता न करे। अगर भारतीय निरमाता अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वसनीयता साबित कर पाए, तो वे मौजूदा टैरिफ अशांति से कहीं आगे तक इन लाभों को सुरक्षित रख सकते हैं।

जहाँ, भारत एक विजेता के रूप में उभर सकता है, वहीं, अन्य अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह व्यापार युद्ध मेक्सिको, कैनडा, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, क्योंकि ये देश चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं (इन्टरमीडियरी गुड्स) पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्शिट्यूट (जी.टी.आर.आई.) की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों, विंड टरबाइन और सेमीकंडक्टरों की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे दुनिया

भर में मँहगाई का दबाव और बढ़ जाएगा। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और भारत के कुल निर्यात का लगभग पाँचवाँ हिस्सा अमेरिका को जाता है। मौजूदा टैरिफ वॉर ने इन संबंधों को और मजबूत करने का अवसर दिया है। दोनों देश जब एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, तो अमेरिकी आपूर्ति मंचला में भारत के शामिल होने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है, खासकर तब, जब अमेरिकी कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में राजनीतिक रूप से स्थिर और कम लागत वाले विकल्पों की तलाश में हैं। अगर भारत इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाए, बंदरागहों का ढाँचा सुधारे और निर्यातकों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराए, तो अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक वरदान साबित हो सकता है, जो उसके निर्यात क्षेत्र को नया रूप देगा और उसे विश्वसनीय वैश्विक मैनुफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा।

अब एनडीए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संभावना है और इसके सदस्य भाजपा या अन्य दलों में शामिल हो जाएंगे। हालाँकि, पिछले दो दशकों की सत्ता विरोधी लहर (एंट्री-इन्कंबेसी) के बावजूद, नीतीश कुमार की महिला मतदाताओं और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में अब भी मजबूत पकड़ है। बड़ी संभावना इस बात की भी है कि यदि यह धारणा मजबूत होती है कि कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इन वर्गों का एनडीए से मोहभंग हो सकता है। बिहार की राजनीति के अनुभवों एवं चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने कई बार विपरीत परिस्थितियों से वापसी की है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि आगे चलकर वे कौन-सा ट्रम्प कार्ड खेलेंगे।

सीट शेयरिंग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चुनाव आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान की घोषणा की है जो 6 और 11 नवंबर को होगा। पहले चरण के नामांकन 6 अक्टूबर से और दूसरे चरण के 13 अक्टूबर से शुरू हुए। लेकिन प्रचार शुरू होने से पहले ही एनडीए को खुले विद्रोह से जूझना पड़ रहा है।

एक नाटकीय घटनाक्रम में, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री जय कुमार सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री ललन कुमार सिंह पर टिकट बेचने और वफादार कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पार्टी की आत्मा को निजी लाभ के लिए नीलाम किया जा रहा है। नेतृत्व ने गठबंधन गणित के नाम पर अपने कैंडर से विश्वासघात किया है।

इधर, भाजपा में भी असंतोष की लहर उठी। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुले मंच से केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान की आलोचना की, उन पर उम्मीदवार चयन में भारी अव्यवस्था का आरोप लगाया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कई मौजूदा विधायक और पूर्व सांसदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतें नहीं सुनी गईं तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे।

आंतरिक संकट ने एनडीए के राज्य और केन्द्रीय नेतृत्व, दोनों को हिला कर रख दिया है। महागठबंधन की बढ़ती गति का मुकाबला करने की उम्मीद कर रहे एनडीए को अब विद्रोह रोकने, नाराज सहयोगियों को मनाने और जन छवि सुधारने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह बगawat एनडीए के भीतर चुनावी संभावनाओं को लेकर गहरी बेचैनी को दर्शाती है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, गठबंधन में घबराहट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आंतरिक दरारों ने इसकी कमजोरी उजागर कर दी है।

मतदान में अब एक महीने से भी कम समय बचा है और एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर से उभर रही है।

तेजस्वी यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लाड़ा था, लेकिन केवल 17 सीटें जीत पाई थी। इस खराब प्रदर्शन के कारण ही, महागठबंधन सरकार नहीं बना सका था।

सूत्रों का कहना है कि अदालत द्वारा लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिये जाने के बाद, कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी और गांधी परिवार, यादव

परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे का इस्तेमाल तेजस्वी यादव पर हमला करने के लिए करेगी।

अब सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा और तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नामित करने का ऐलान पटना में किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी आज देर शाम वापस बिहार खाना हो गए हैं।

करुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को रेली के दौरान भगदड़ हुई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 41 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

शीर्ष अदालत ने टीवीके और पनीरसेल्वम पिचार्ईमुथु, एस प्रभाकरन, सेल्वराज पी, जी एस मणि तथा अन्य की याचिकाओं पर अपना यह आदेश पारित किया। याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

हमास ने बीस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में कम से कम बीस देश भाग ले रहे हैं। कैदियों की अदला-बदली देखने और इजरायली संसद को संबोधित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मिस्र के इस तटीय शहर पहुंचे, जहाँ वे क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में बीस से अधिक देश भाग ले रहे हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी होगी और हर मुद्दे

पर सहमति बनाना एक कठिन और समय लेने वाला काम साबित होगा।

तीन विद्वानों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था। यह परिवार बहुत मुश्किलों से नाज़ी नरसंहार में बच गया था।

फिलिप अधियन एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पेरिस स्कूल ऑफ

इकोनॉमिक्स में अध्यापन करते रहे हैं। पीटर होवित कनाडाई अर्थशास्त्री हैं, जो नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त करने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

TRUE VALUE

THIS Diwali

CARS MADE AFFORDABLE

INSTALLMENT AS LOW AS ₹59 PER DAY ONLY#

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

EASY FINANCE OPTIONS* AVAILABLE

TRUST

✓ VERIFIED CAR HISTORY**

✓ AVAIL 3 FREE SERVICES** @5000++ MARUTI SUZUKI SERVICE STATIONS

For enquiry, call 1800 102 1800 | Visit www.marutisuzukitruevalue.com

*T&C Apply. For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Financing is at the sole discretion of the financiers. **Verified Car History & Warranty applicable on True Value certified cars. Free service is applicable on labour charges only. Images used are for illustration purposes only. *Loan amount considered is Rs 100 000. Terms of loan is 84 months @ ROI of 11% per annum. Down payment may vary as per value of the car. Finance is at the sole discretion of the financier and may vary basis customer profile.

QUALITY

✓ 376 QUALITY CHECK POINTS

✓ UP TO 1 YEAR WARRANTY**

Download the App here.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Alwar: Near Alwar Public School, Jaipur Road, Alwar, MG Motors: 7240012934, 7728892248, 7073130666 | Opposite Matila police station Alwar bypass Road Bhiwadi, Fortune Cars: 8875001550, 9214094335 | Manhar Villa, Near Jail Circle, Vijay Nagar Road, Alwar, Fortune Cars: 7230029310, 7230029304. Bharatpur: After Barso, Before Shaheed Petrol Pump, Agra Road, Bharatpur, T.M. Motors: 9772965965, 9772772999.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधमा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आखड़ मैने रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●